

महंगे गन्ने से शुगर मिलों के मार्जिन पर चोट

बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान और धामपुर शुगर के मुनाफे में कमी की आशंका

[सूरज साउकर ईटीआईजी]

गन्ने का स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव प्राइस (एसएपी) बढ़ाने के उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले से लोकल शुगर मिलों को निराशा हुई है। इन्हें हाल में शुगर के दाम बढ़ने का फायदा अब नहीं मिल सकेगा। बलरामपुर चीनी मिल्स, बजाज हिंदुस्तान और धामपुर शुगर जैसी कंपनियों के मुनाफे में करेंट शुगर सीजन में भी कमी रह सकती है।

उत्तर प्रदेश सरकार ने करेंट सीजन (अक्टूबर 2012-सितंबर 2013) के लिए गन्ने का एसएपी 17 पैसे बढ़ाकर 280 रुपये क्विंटल कर दिया है। गन्ने के प्रोडक्शन में कमी के अनुमान के चलते पिछले कुछ महीनों में शुगर के दाम (एक्स-कानपुर) 14 पैसे से ज्यादा बढ़े हैं।

इस साल सामान्य से कम मानसून के चलते गन्ने का प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है। इंडस्ट्री के आकलन के मुताबिक, पिछले सीजन के 2.6 करोड़ टन के मुकाबले इस बार शुगर प्रोडक्शन 2.4 करोड़ टन रहने की उम्मीद है, जबकि उपभोग 2.2 करोड़ टन के लेवल पर ही रहने की संभावना है। इस वजह से पिछले कुछ महीने में शुगर के दाम बढ़े हैं। इसकी झलक सितंबर क्वार्टर में देखने को मिली है। शुगर का करेंट एक्स-मिल प्राइस 33 रुपये है। एसएपी में बढ़ोतरी से कंपनियों को शुगर डिवीजन में मार्जिन में कमी का सामना करना पड़ेगा। ऐसा माना जा रहा है कि लागत को कवर करने के लिए एक्स-मिल प्राइस को बढ़ाकर करीब 35 रुपये किलो करने की जरूरत है। सामान्य तौर पर मार्केट प्राइस से चार रुपये कम एक्स-मिल प्राइस रहता है।

हालांकि, रीजनल शुगर मिलों की हालत उतनी बुरी भी नहीं है। एक तरफ जहां देशभर में प्रोडक्शन कम रहेगा, वहीं यूपी में इस साल प्रोडक्शन 15 पैसे ज्यादा रह



प्रोडक्शन में आई कमी

- इस साल सामान्य से कम मानसून के चलते गन्ने का प्रोडक्शन कम रहने की उम्मीद है
- पिछले सीजन के 2.6 करोड़ टन के मुकाबले इस बार शुगर प्रोडक्शन 2.4 करोड़ टन रहने की उम्मीद, इस वजह से शुगर के दाम बढ़े हैं
- एसएपी में बढ़ोतरी से भी कंपनियों को शुगर डिवीजन में मार्जिन में कमी झेलना होगा

सकता है। प्रोडक्शन बढ़ने के साथ डिस्टिलरी और कोजेनेरेशन डिवीजन में सुधार की उम्मीद है। उधर, शुगर सेक्टर को डीकंट्रोल करने के उपायों पर भी नजर लगी है। लेवी कोटा खत्म करने और मार्केटिंग मैकेनिज्म हटाने

से जैसे कुछ प्रमुख उपाय डीकंट्रोल के तहत आते हैं। लेवी मैकेनिज्म के तहत शुगर मिलों को कुल प्रोडक्शन का 10 पैसे हिस्सा पब्लिक डिस्ट्रिब्यूशन सिस्टम के लिए देना पड़ता है। यह सामान्य तौर पर मार्केट प्राइस से कम रेट पर होता है। रिलीज मैकेनिज्म के तहत मिलों के लिए हर महीने मार्केट में शुगर बेचने का कोटा तय किया जाता है। डीकंट्रोल उपायों के तहत अगर शुगर मिलों से ऐसे प्रतिबंध हटते हैं, तो कंपनियों को इससे लॉन्ग-टर्म में फायदा होगा। करेंट स्टॉक प्राइस पर बलरामपुर चीनी, बजाज हिंदुस्तान और धामपुर शुगर के स्टॉक बुक वैल्यू के 0.7-1.1 गुना ज्यादा पर टूट कर रहे हैं। अगर रंगराजन कमेटी के डीकंट्रोल से जुड़े कुछ उपाय लागू होते हैं, तो कुछ कंपनियों के स्टॉक में मार्केट की दिलचस्पी बढ़ सकती है।